

प्रेषक

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

प्रोत्ता ५

1. समर्स्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समर्स्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समर्स्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (व०आ०-सा०नि०) अनुभाग-७

देहरादून, दिनांक 22 मई, 2008

विषय :-कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपार्टमेंट आधार पर किये जाने वाले निर्णय कार्य एवं साज-सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार का निर्धारण।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या ए-2-87/दस 27-17(4)/75 मिनांग 27 फरवरी, 1997, जिसके अन्तर्गत कार्यदायी, संस्थाओं द्वारा डिपार्टमेंट के रूप में किये जा रहे कार्यों पर प्रतिशत-प्रभार की दर पुनरीक्षित की गई है, (सुलग सन्दर्भ हेतु टंकित प्रति रालग्न) का एतद्वारा अतिकमित करते हुए शाशन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रतिशत प्रभार (रीन्टेज प्रभार) की व्यवरण्या तत्काल प्रभाव सिन्हानुसार निर्धारित की गई है :-

1. सैन्टेज प्रगार की दर :-

(1) उन निर्माण कार्यों जिनकी लागत ₹0 1,00 करोड़(₹0 1.00 एक करोड़) तक है लागत का 10% (दरा प्रतिशत)

(2) ₹0 1,00(एक) करोड़ से अधिक परन्तु ₹0 5,00 (पांच) करोड़ तक लागत का 09% (नौ प्रतिशत)

(3) ₹0 5,00(पांच) करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्य लागत का 08% (आठ प्रतिशत)

2 वास्तुविद सेवाएँ (Architectural Services) :-

निर्माण कार्य के लिए वारत्तुविद रोकाए गाल्का विभाग द्वारा यदि रीप किसी तृतीय पक्ष से आडटसोर्सिंग द्वारा प्राप्त की जाती हैं तो उरा दस्ता में निर्माण ईकाई/कार्यदायी संस्था को 02% (दो प्रतिशत) सैन्टज प्रधार कर देय होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मानक लिंजाइन बाले भवन निर्माण कार्यों को छोड़कर रु0 1.00 करोड (लाख से एक करोड़) से अधिक लागत बाले भवन निर्माण कार्यों में तृतीय पक्ष से वारत्तुविद

सेवाएँ अनिवार्य रूप से ली जायेंगी। वारस्तुविद सेवाओं की अधिप्राप्ति ग्राहक विभाग अथवा कार्यदायी संस्था के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रोवियोरमेन्ट नियमावली 2008 के अनुसार की जाएगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वारस्तुविद सेवाओं में, निम्नलिखित अगं समिलित होंगे:-

- (1) कन्सेप्ट प्लानिंग एवं स्कैच;
- (2) अनुमानित लागत, ड्राइंग एवं विशिष्टियों;
- (3) विस्तृत आगणन, ड्राइंग एवं विशिष्टियों;
- (4) नियिदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध गठन सम्बन्धी सलाह;
- (5) विस्तृत वर्किंग ड्राइंग/डिजाइन/गुणवत्ता नियंत्रण एवं
- (6) निर्माण के दौरान स्थलीय भ्रमण द्वारा पर्यवेक्षण।

3. लागत व निर्माण अवधि में वृद्धि को हतोत्साहित किया जाना:

- (1) जिन निर्माण कार्यों की निर्माण अवधि 18 (अठारह) माह तक होगी उनमें लागत का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
- (2) शेष निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निर्माण कार्य पूर्ण करने से कार्यदायी संस्था की ओर से किये गये विलम्ब की दशा में निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि उपरान्त अग्रेस्टर तीन माह तक के विलम्ब की दशा में प्रतिमाह 0.1% (दशमलव एक प्रतिशत) तथा उससे अधिक विलम्ब की दशा में प्रतिमाह 0.25% (दशमलव दो पाँच प्रतिशत) की कटौती कार्यदायी संस्था को देय सैन्हेज प्रभार राखी जायेगी।
- (3) ग्राहक विभाग व निर्माण ईकाई (कार्यदायी संस्था) के बीच निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तीन निर्माण के विभिन्न वरणों तक तथा पूर्ण निर्माण के लिए अग्रिम नियत की जायेगी एवं इस निर्माण अवधि को समिलित करते हुए दोनों के मध्य एम०आ००४००/अनुबन्ध उपरान्त अनुबन्ध उपरान्त अनुबन्ध में धनराशि मांग की समयसारिणी (fund flow schedule), कार्यमाजना एवं निर्माण कार्य प्रगति की समयसारिणी/लक्ष्य भी इगरित किया जायेगा। ग्राहक विभाग द्वारा निर्माण ईकाई को अग्रेस्टर किशते तब ही अवमुक्त की जायेगी जब पूर्व किश्तों के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उक्तानुसार नियत किये गये चरणबद्ध निर्माण लक्ष्य को निर्धारित समयावधि के सापेक्ष पूर्ण कर लिए जाने की स्थिति प्रस्तुत कर दी जायेगी। इस हेतु मानक एम०आ००४००/अनुबन्ध का आलेख वित्त विभाग द्वारा पृथक से तैयार किया जायेगा परन्तु तब तक प्रत्येक प्रकरण में ग्राहक विभाग उपरोक्तानुसार यथोचित रूप से कार्यदायी संस्था से undertaking अवश्य सम्पादित कर लेंगे।

4. अनुश्रवण / गुणवत्ता नियंत्रण :-

प्रत्येक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। ₹० ०५.०० करोड (रुपये पाँच करोड़) रो अधिक लागत के निर्माण कार्य हेतु यह व्यवस्था वाध्यकारी होगी। अधिक लागत के निर्माण कार्य हेतु यह व्यवस्था वाध्यकारी होगी। अनुश्रवण व अनुश्रवण के लिए तृतीय पक्ष के चयन आदि कार्य गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण के लिए तृतीय पक्ष के चयन आदि कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं उनका भुगतान भी नियोजन विभाग के बजट से किया जायेगा। ग्राहक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियोजन विभाग के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण कार्य हेतु तृतीय पक्ष को निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के समय तक अनुश्रवण कार्य हेतु तृतीय पक्ष को निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के समय तक नियोजित कर लिया जाय। गुणवत्ता नियंत्रण व अनुश्रवण हेतु नियोजित किया जायेगा कि नियोजन विभाग के उपलब्ध रिपोर्ट ग्राहक विभाग, वित्त विभाग व तृतीय पक्ष की नियमित चरणवद्ध रिपोर्ट ग्राहक विभाग, वित्त विभाग व नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राहक विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में इंगित की गई द्विटियों का निराकरण व कार्यवाही समय से कर लिया जाये तथा सुझावों पर कार्यवाही की जाये।

5. साज-सज्जा कार्य हेतु सैन्टेज प्रभार :

साज-सज्जा, उपकरण आदि कार्य कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराये जाने की दशा में सैन्टेज प्रभार मात्र ०१% (एक प्रतिशत) देय होगा।

कृपया रैन्टेज प्रभार व सम्बन्धित बिन्दुओं पर तदानुसार कड़ाई व अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीरा,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: १६३ /xxvii(7)/2007 / प्रतिलिपि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अविश्वप्त नहीं होती हेतु प्रेपित-

- 1- महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 6- वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वैतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं 261, नार्थ लाक, नई दिल्ली-110001
- 7- सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- महानिवन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
- 10- रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिशनर, कानपुर / देहरादून।
- 11- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 12- स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 13- निदेशक, एनोआईसी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 14- टी०ए०सी० (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा (मेरे
नाम
(टी०ए०सी०)
अपर सचिव